
इकाई 7 आर्थिक एवं मौद्रिक संघ

संरचना

- 7.0 प्रस्तावना
- 7.1 उद्देश्य
- 7.2 आर्थिक एकीकरण
- 7.3 आर्थिक एवं मौद्रिक संघ की उत्पत्ति तथा पृष्ठभूमि
 - 7.3.1 आर्थिक एवं मौद्रिक संघ की स्थापना
- 7.4 यूरो में प्रवेश
- 7.5 यूरो के लाभ
- 7.6 विष्व अर्थव्यवस्था में यूरो
 - 7.6.1 यूरो तथा भारत
- 7.7 सारांश
- 7.8 अभ्यास प्रश्न
- 7.9 संदर्भ तथा कुछ उपयोगी पुस्तकें

7.0 प्रस्तावना

समकालीन विष्व में क्षेत्रीय आर्थिक संघटन के महत्व में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। इससे पहले इस शब्दावली का प्रयोग आर्थिक सम्बन्धों में किसी भी प्रकार के सहयोग के रूप में किया जाता था। बाद में, इसका प्रयोग व्यापार-अर्थशास्त्रियों (trade-economists) द्वारा विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं के मुक्त व्यापार क्षेत्रों के अपेक्षाकृत बड़े समूहों में विलय के रूप में किया गया। समकालीन चर्चाओं में "आर्थिक क्षेत्रीयवाद" का प्रयोग आर्थिक सहयोग के कुछ विषिष्ट अवयवों की स्थापना द्वारा दो या अधिक राज्यों में व्यापारिक बाधाओं को हटाना माना जाता है।

इस इकाई में, आर्थिक एकीकरण की प्रक्रिया यूरोपीय संघ में किस प्रकार हुई तथा कैसे कार्य कर रही है, पर विस्तृत चर्चा करेंगे।

7.1 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप निम्नलिखित विषयों को समझने के योग्य हो जाएँगे:

- आर्थिक क्षेत्रवाद के विभिन्न स्वरूपों की व्याख्या;
- आर्थिक एवं मौद्रिक संघ की पृष्ठभूमि, विभिन्न चरण तथा संस्थागत प्रबंधों की व्याख्या;
- एकल यूरोपीय मुद्रा के लाभ;
- यूरो की अन्तर्राष्ट्रीय भूमिका; और
- भारत पर यूरो के परिणाम।

7.2 आर्थिक एकीकरण

यूरोप में यह आर्थिक संघटन किस प्रकार स्थापित हुआ और यह किस प्रकार कार्य कर रहा है इनकी चर्चा हम इस इकाई में करेंगे। व्यावहारिक स्तर पर आर्थिक क्षेत्रीयवाद का अर्थ आर्थिक संघटन की गहराई की प्रक्रिया से लिया जाता है जैसा कि तालिका 1 में दर्शाया गया है। यह ऐसी प्रक्रिया है जिससे विभिन्न सदस्य देशों में सहयोग की सीमा पर निर्भर विभिन्न रूप हो सकते हैं। यह मुक्त व्यापार समझौता, शुल्क संघ, सांझा बाजार, अथवा आर्थिक संघ से लेकर राजनीतिक संघ तक हो सकता है।

पिछले 50 वर्षों में आर्थिक संघटन के कई स्वरूप प्रस्तावित किए गए तथा विश्व के कई भागों में उन्हें कार्यान्वित भी किया गया परन्तु पिछले 15 वर्षों में यह अत्यधिक विकसित

हुआ है। बहुपक्षीय व्यापारिक व्यवस्था द्वारा संचालित विष्व व्यापार संगठन के साथ-साथ विष्व व्यापार ढाँचे में अब क्षेत्रीय व्यापारिक प्रबंधों के जटिल ढाँचे की प्रभुता भी बढ़ती जा रही है। आरंभ में आर्थिक क्षेत्रीयवाद को भौगोलिक दृष्टिकोण से निरन्तर राज्यों में आर्थिक सहयोग माना जाता था। परन्तु हाल के वर्षों में पार-क्षेत्रीय देशों में द्वि-पक्षीय समझौतों के उदाहरण भी देखने को मिले हैं। वे देश जो आरंभ में इन प्रबंधों से बाहर रहे, अब इनमें सम्मिलित होने का प्रयास कर रहे हैं। क्षेत्रीय-आर्थिक संघटन पर पिछले वर्षों की शैक्षणिक चर्चाओं का सम्बन्ध इन्हें व्यापारिक उदारीकरण के समर्थक अथवा बाधक के रूप में परिभाषित करता रहा है। चर्चा का प्रमुख विषय यह रहा है कि क्या क्षेत्रीय एकीकरण वैश्वीकरण का पूरक हैं या इसका विरोधी। कुछ लेखकों का मानना है कि ये प्रबंध बहुपक्षीय व्यापारिक व्यवस्था में बाधक हैं। कुछ अन्य लेखकों का विचार है कि यह "नया क्षेत्रवाद", "पुराने क्षेत्रवाद" से सर्वथा भिन्न है। इनका तर्क है कि ये प्रबंध सदस्य देशों की विष्व अर्थव्यवस्था में भागेदारी को सरल बनाते हैं।

तालिका 1 : क्षेत्रीय संघटन की गहराई के चरण (Stages of Deepening of Regional Integration)

संघटन की गहराई	आर्थिक उदारीकरण	सांझी वाणिज्यिक नीति	मुक्त आवागमन कारक	वित्तीय मुद्रा नीति	सांझी सरकार
मुक्त व्यापार समझौता	→				
शुल्क यूनियन	→	→			
सांझा बाज़ार	→	→	→		
आर्थिक संघ	→	→	→	→	
राजनीतिक संघ	→	→	→	→	→

स्रोत: ग्रे. पी. सेंगसन ऑफ स्टीफन वुडकुक, *मल्टीटेबुलुजन एण्ड ईकॉनॉमिक इंटीग्रेशन : दी रिसेंट एक्सपीरियन्स*

7.3 आर्थिक एवं मौद्रिक संघ की उत्पत्ति तथा पृष्ठभूमि

क्षेत्रीय आर्थिक संघटन का सबसे प्रभावशाली तथा महत्वपूर्ण उदाहरण यूरोपीय संघ है जो एक मुक्त व्यापार क्षेत्र से परिपूर्ण आर्थिक तथा मौद्रिक संघ (Economic and Monetary Union; EMU) में विकसित हुआ है। कई बार आर्थिक एवं मौद्रिक संघ की यूरोपीय मौद्रिक संघ के रूप में गलत व्याख्या की जाती है। यह केवल मुद्रा का ही नहीं बल्कि आर्थिक नीतियों का भी समन्वय तथा संयोजन है। जैसा कि हम बाद में चर्चा करेंगे, आर्थिक एवं मौद्रिक संघ के तीन चरण हैं जिनमें केवल तीसरे चरण का अर्थ सांझी मुद्रा का अंगीकरण है।

यूरोप के नागरिकों के बीच निकटतम सम्बन्ध स्थापित करने के उद्देश्य से 1957 में रोम की संधियों पर हस्ताक्षर किए गए। हालाँकि वस्तुओं, सेवाओं, पूँजी तथा लोगों का मुक्त आवागमन इन संधियों का मूल उद्देश्य था तथापि 1980 के दशक तक इस आवागमन में काफी अवरोध बने रहे। 1985 में कॉकफील्ड रिपोर्ट में एकल आन्तरिक बाज़ार की दिशा में 280 बचे हुए भौतिक, तकनीकी तथा वित्तीय अवरोधों की चर्चा की गई। इन मुद्दों को सुलझाने के लिए यूरोपीय आयोग ने 1986 में एकल यूरोपीय अधिनियम (Single European Act) पारित किया जिसमें व्यापार के इन सभी अवरोधों को हटा कर एकल बाज़ार स्थापित करने की कोषिष की गई तथा आर्थिक संघटन के लिए दबाव बढ़ाया गया।

वर्तमान साहित्य में आर्थिक एवं मौद्रिक संघ एक ऐसी इकाई का नाम है जिसमें सदस्य देशों में चल रही आर्थिक तथा मौद्रिक नीतियों की समन्वय प्रक्रिया तथा एकल मुद्रा यूरो के प्रचलन के संदर्भ में लिया जाता है। मौद्रिक संघटन का अर्थ है विनिमय दर का संघ तथा पूँजी बाज़ार संघटन। यह समन्वय एकल मुद्रा के अस्तित्व के बिना भी सम्पन्न हो सकता था यदि सदस्य देशों ने परस्पर विनिमय दरें स्थाई तथा अपरिवर्तनीय स्तर पर निश्चित कर ली होतीं। व्यावहारिक स्तर पर इसका अर्थ होगा वित्तीय नीतियों में समन्वय, विदेशी मुद्रा का सांझा निकाय तथा केन्द्रीकृत बैंक।

दूसरे देशों से सामान और सेवाएँ खरीदने के लिए निवेशक तथा उपभोक्ता अपनी मुद्रा खरीदते हैं क्योंकि प्रत्येक देश की मुद्रा भिन्न होती है। अतः इसके लिए एक विनिमय दर की आवश्यकता पड़ती है जो अनिवार्यतः विदेशी मुद्रा इकाई की घरेलू कीमत होती है। सैद्धान्तिक तौर पर ये विनिमय दरें दो प्रकार की होती हैं जैसे *स्थिर निश्चित विनिमय दर*, तथा *अस्थायी विनिमय दर*। स्थिर निश्चित विनिमय दर एक ऐसी परिस्थिति होती है जिसमें देश अपनी मुद्रा के विदेशी मूल्य में किसी तरह के परिवर्तन की इजाजत नहीं देते। इस स्थायी विनिमय दर को सुनिश्चित रखने के लिए राष्ट्रीय सरकारें समय-समय पर विदेशी मुद्रा बाज़ार में हस्तक्षेप करती रहती है। इसके विपरीत अस्थायी विनिमय दर में विदेशी मुद्रा बाज़ार में बाज़ार-शक्तियों को हावी होने का अवसर दिया जाता है ताकि वे भुगतान का स्वचल संतुलन प्राप्त कर सकें। इसका अर्थ है कि विदेशी मुद्रा बाज़ार में सरकारें हस्तक्षेप नहीं करती। व्यावहारिक दृष्टिकोण से सांसारिक स्तर पर अधिकतर देशों की स्थिति इन दोनों विकल्पों के बीच की है।

7.3.1 आर्थिक एवं मौद्रिक संघ की स्थापना

1971 तक यूरोपीय आर्थिक समुदाय के मौद्रिक प्रबंध ब्रैटन वुड्स व्यवस्था (Bratton Woods System; BWS) के अन्तर्गत कार्य कर रहे थे। ब्रैटन वुड्स व्यवस्था निश्चित विनिमय दरों पर आधारित अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक संरचना थी जो अमेरिका तथा ब्रिटेन द्वारा 1944 में बनाई गई थी। इस व्यवस्था की मुख्य विशेषता यह थी कि इसे अपनाने वाले देश को ऐसी मुद्रा नीति अपनानी जरूरी थी जो इसकी मुद्रा के विनिमय दर को सोने की कीमत के संदर्भ में निश्चित मूल्य की सीमाओं (\pm प्रतिषत) में रखे। अदायगी के अस्थायी असन्तुलन की कमी को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पूरा करेगा। व्यावहारिक स्तर पर इसका अर्थ था कि विनिमय दरें निश्चित रहेंगी तथा सभी मुद्राएँ अमरीकी डॉलर के साथ जुड़ी होंगी। अमरीकी डॉलर की सोने के साथ सममूल्यता थी (1 ऑंस सोना = 55 अमरीकी डॉलर)। इसका अर्थ था कि डॉलर को किसी भी समय सोने में बदला जा सकता था। डॉलर के साथ सममूल्यता बनाए रखने के लिए सभी बैंकों को डॉलर के भण्डार रखने पड़ते थे। यह व्यवस्था कुछ देर तक तो काफी अच्छी चली परन्तु बाद में मौद्रिक

आदान-प्रदान में प्रसार, बहुलपक्षीय आर्थिक शक्तियों के उदय तथा बढ़ते हुए अमरीकी व्यापारिक घाटे के कारण कई तरह के संरचनागत असंतुलन उत्पन्न होने लगे। 1971 में अमेरिका ने डॉलर का सोने में परिवर्तन निलम्बित कर दिया जिसके कारण यह व्यवस्था चरमरा गई।

ब्रैटन वुड्स व्यवस्था के पतन के बाद यूरोपीय आर्थिक समुदाय (EEC) के सदस्यों ने ब्रिटेन, आयरलैण्ड, डेनमार्क तथा नार्वे के साथ मिलकर यह निर्णय लिया कि डॉलर के विरुद्ध 2.25 प्रतिशत से अधिक उतार-चढ़ाव को रोककर वे परस्पर निश्चित विनिमय दर अपनाएँगे। इस प्रबंध को "सुरंग में यूरोपीय सांप" (European Snake in the Tunnel) का नाम दिया गया क्योंकि विदेशी मुद्राओं, विशेषकर डॉलर, के विरुद्ध यूरोपीय समुदाय की मुद्राओं को सामूहिक स्तर पर उतारा गया। तेल संकट, डॉलर की कमजोरी, तथा अन्य घटनाओं ने विनिमय दर के स्थायित्व में बाधा पहुँचाई तथा दो सालों के भीतर ब्रिटिश पाउंड, आइरिश पत (Punt), डेनिश क्रोन (Krone), इटालियन लीरा इस प्रबन्ध से बाहर निकल गए तथा सुरंग का यह यूरोपीय सांप केवल जर्मन, बेनेलक्स तथा डेनमार्क की मुद्राओं तक सीमित रह गया।

इन अस्थिर परिस्थितियों के चलते, 1969 में यूरोपीय शिखर सम्मेलन ने आर्थिक एवं मौद्रिक संघ को अपना औपचारिक राजकीय उद्देश्य बना लिया। 1970 में वरनर रिपोर्ट (Werner Report) में आर्थिक एवं मौद्रिक संघ को तीन चरणों में अगले दस वर्षों में पूरा करने की योजना बनाई गई। परन्तु 1970 के दशक में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा संकट तथा 1973 में तेल संकट के कारण हुई विष्व आर्थिक मंदी के चलते ये योजनाएँ वास्तविक रूप नहीं ले सकीं।

1979 में यूरोपीय मौद्रिक व्यवस्था (European Monetary System; EMS) की रचना एक महत्वपूर्ण कदम था। हालाँकि यह मौद्रिक संघ नहीं था, फिर भी इसने सदस्य देशों की मुद्राओं को वृहतर स्थायित्व प्रदान किया तथा उनकी आर्थिक/मौद्रिक नीतियों में बेहतर समन्वय तथा समाभिरूपता (convergence) स्थापित की। यूरोपीय मौद्रिक व्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग थे : यूरोपीय मुद्रा इकाई (European Currency Unit; ECU), यूरोपीय मौद्रिक

सहयोग कोष (European Monetary Cooperation Fund; EMCF) तथा विनिमय दर रचनातंत्र (Exchange Rate Mechanism; ERM) ।

यूरोपीय समुदाय की विभिन्न सरकारों तथा संगठनों के बीच लेन-देन यूरोपीय मुद्रा इकाई की भूमिका हिसाब की इकाई (Unit of Account) के रूप में थी। यह यूरोपीय संघ की विभिन्न मुद्राओं से निर्मित एक सांकेतिक मुद्रा थी। यह विधिमान्य चलार्थ (legal tender) भी नहीं थी और न ही यह नोटों के रूप में थी। इसका मूल्य घटक मुद्राओं के आनुपातिक मूल्य के औसत के रूप में आंका जाता था। इसका अनुपात किसी देश-विषेय की कुल राष्ट्रीय उत्पाद तथा अन्तर-यूरोपीय समुदाय व्यापार में इसके अंश के प्रतिषत के आधार पर निश्चित किया जाता था। यूरोपीय समुदाय के सदस्य देशों के बीच लेन-देन को सरल बनाने के लिए 1973 में यूरोपीय मौद्रिक सहयोग कोष की स्थापना की गई। सभी सदस्य देशों ने अपने सोने तथा डॉलर के भण्डार का 20 प्रतिषत इस कोष में जमा कर दिया तथा बदले में इसी मूल्य की यूरोपीय मुद्रा इकाइयाँ प्राप्त कर लीं।

विनिमय दर रचनातंत्र (Exchange Rate Mechanism; ERM) सदस्य देशों के बीच मुद्राओं के सापेक्षिक मूल्य में उतार-चढ़ाव को कम करने का यंत्र था। इसने सभी भागेदारी मुद्राओं को यूरोपीय मुद्रा इकाई के विरुद्ध एक केन्द्रीय विनिमय दर (Central Exchange Rate; CER) प्रदान की, जिसके परिणामस्वरूप सभी सदस्य देशों को एक-दूसरे के विरुद्ध केन्द्रीय विनिमय दरें प्राप्त हो गईं। इस रचनातंत्र में भाग लेने वाली मुद्राओं को इस केन्द्रीय विनिमय दर के दोनों तरफ एक उच्च तथा निम्न सीमा दे दी गई जिसके बीच ये मुद्राएँ उतार-चढ़ाव कर सकती थीं। यह सम्पूर्ण व्यवस्था परस्पर समर्थन तथा सामूहिक क्रिया के आधार पर सम्पादित की गई। ऐसी आशा की गई कि विनिमय दर रचनातंत्र विनिमय दर को स्थायित्व प्रदान करने में सहायता ही नहीं करेगा अपितु यूरोप के अन्दर व्यापार को प्रोत्साहित करेगा तथा मुद्रा स्फीति को भी रोकेगा। 1992 में विनिमय दर रचनातंत्र संकट के समय इसके 10 सदस्य थे। स्पेन 1987 में इसका सदस्य बना, यू.के. 1990 में, तथा पुर्तगाल 1992 में। कमजोर अर्थव्यवस्था के कारण ग्रीस इसका सदस्य नहीं बन सका तथा लज़मबर्ग ने अपनी मुद्रा बैल्जियम फ्रैंक पर आधारित रखी। 1992 में जब कई देश अपनी मुद्राओं को सीमा के अन्तर्गत नहीं रख पाए तो विनिमय दर रचनातंत्र

वस्तुतः चरमरा गया। यह घटना काले बुधवार (Black Wednesday) के नाम से प्रसिद्ध है जब ब्रिटिश पाउंड को इस रचनातंत्र से निकलने के लिए मजबूर होना पड़ा। इटालियन लीरा ने भी इसका साथ छोड़ दिया तथा स्पेन को अपने पेस्ता (Peseta) का अवमूल्यन करना पड़ा।

7.4 यूरो में प्रवेश

जून 1988 में यूरोपीय परिषद् ने सिद्धान्त रूप में आर्थिक एवं मौद्रिक संघ स्थापित करने का निष्चय किया। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष जैक्वास डेलेरस की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया जिसे मौद्रिक संघ के विभिन्न चरणों का अध्ययन करने का कार्य भार सौंपा गया। इस समिति ने सुझाव दिया कि आर्थिक एवं मौद्रिक संघ तीन चरणों में सम्पादित किया जाना चाहिए। डलरोस समिति की सिफारिशों के आधार पर जून 1989 में यूरोपीय परिषद् ने यह निर्णय लिया कि 1 जुलाई 1991 से सदस्य देशों के बीच पूँजी के आवागमन पर सभी प्रकार के बंधन समाप्त कर दिए जाएँ। आर्थिक एवं मौद्रिक संघ की स्थापना की दिशा में यह पहला कदम था। अगले दो चरणों के लिए आवश्यक कानूनी तथा संस्थागत ढाँचा स्थापित करने के लिए 1991 में एक अन्तर-सरकारी सम्मेलन बुलाया गया। इन सभी प्रत्यनों का परिणाम यूरोपीय संघ संधि (Treaty of European Union) था जिस पर दिसम्बर 1991 में समझौता हुआ तथा 7 फरवरी 1992 में मैस्ट्रिक में हस्ताक्षर हुए। तथापि इस संधि के अनुमोदन में हुए विलम्बों के कारण यह 1 नवम्बर 1997 को ही लागू हो सकी। इस संधि में साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया गया कि जो देश एकल मुद्रा अपनाना चाहता है उन्हें कुछ आर्थिक मानदण्डों का अनुसरण करना होगा। इस नए *अभिसरण मानदण्ड (Convergence criteria)* की मुख्य बातें थी: नीची मुद्रा स्फीति, दुरुस्त सार्वजनिक वित्त, निम्न ब्याज दरें तथा स्थायी विनिमय दरें। इसके अतिरिक्त प्रत्येक देश अपने राष्ट्रीय केन्द्रीय बैंकों की राजनीतिक स्वतंत्रता की गारंटी भी देगा। विषिष्ट रूप से किसी भी देश के आर्थिक एवं मौद्रिक संघ में सम्मिलित होने के लिए निम्नलिखित शर्तें रखी गईं:

- मुद्रा स्फीति की दर सर्वोत्तम निष्पादन करने वाले तीन सदस्य देशों की औसत से 1.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- दीर्घकालीन ब्याज दरें निम्न मुद्रा स्फीति वाले राज्यों की पिछले 12 महीनों की औसतन दर से 2 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- विनिमय दरों का उतार-चढ़ाव कम से कम दो वर्षों के विनिमय दर रचनातंत्र की सामान्य सीमाओं के अन्तर्गत होना चाहिए।
- सरकारी ऋण/ सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात 60 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए परन्तु यदि यह अत्यधिक ह्रासमान हो तो उच्चतर अनुपात की आज्ञा दी जा सकती है।
- सरकार का घाटा सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में 3 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए, हालाँकि अस्थायी तौर पर इस प्रतिशत को थोड़ा बढ़ाया जा सकता है।

व्यापक स्तर पर, आर्थिक एवं मौद्रिक संघ का प्रथम चरण 1 जुलाई 1990 से लेकर 31 दिसम्बर 1993 तक चला। इस चरण में मैस्ट्रिक संधि लागू होने से पहले ही प्रारंभिक उपायों को अन्तिम रूप दिया गया। इस चरण की मुख्य विशेषता – सभी राज्यों की आर्थिक नीतियों में नजदीकी समन्वय तथा यूरोपीय संघ के अन्तर्गत पूँजी के स्वतंत्र आवागमन के लिए आन्तरिक बन्धन हटाना था। आर्थिक एवं मौद्रिक संघ का दूसरा चरण 1 जनवरी 1993 में आरंभ हुआ तथा यह 31 दिसम्बर 1998 तक चला। इस चरण में सदस्य-राज्यों को यूरो अपनाने के लिए तैयार किया गया। इस चरण के मुख्य तत्व थे – यूरोपीय संघ बनाम अन्य देशों के बीच पूँजी के आवागमन तथा अदायगी में उदारीकरण को बढ़ावा देना, केन्द्रीय बैंकों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र को वित्तीय सहायता देने पर रोक लगाना, सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों की वित्तीय संस्थाओं तक विशेषाधिकृत पहुँच पर रोक लगाना, अत्यधिक सरकारी घाटे से बचाव, तथा फ्रैंकफर्ट में यूरोपीय मौद्रिक संस्था

(European Monetary Institute; EMI) की स्थापना करना आदि थे। यूरोपीय मौद्रिक संस्था के प्रमुख कार्य थे केन्द्रीय बैंकों में सहयोग बढ़ाना, मौद्रिक नीति समन्वय तथा केन्द्रीय बैंकों की यूरोपीय व्यवस्था (European System of Central Bank; ESCB) की स्थापना ताकि एकल मौद्रिक नीतियों का संचालन ताकि तीसरे चरण के लिए एकल मुद्रा की रचना संभव हो सके। केन्द्रीय बैंकों की यूरोपीय व्यवस्था यूरोपीय संघ की केन्द्रीय बैंकिंग व्यवस्था है जो यूरोपीय केन्द्रीय बैंक तथा यूरोपीय संघ के सभी सदस्यों के केन्द्रीय बैंकों से मिलकर बनती है।

1 जून 1998 में यूरोपीय मौद्रिक संस्था में से एक नए यूरोपीय केन्द्रीय बैंक (European Central Bank; ECB) की स्थापना की गई जिसने 1 जनवरी 1999 को सांझी मौद्रिक नीति के कार्यान्वयन का भार संभाला। यूरोपीय केन्द्रीय बैंक की अधिषासी परिषद् (Governing Council) में कार्यकारी बोर्ड के छह सदस्य तथा 12 यूरो क्षेत्र राज्यों के केन्द्रीय बैंकों के 12 गवर्नर होते हैं। यह अधिषासी परिषद् महीने में दो बार मिलती है। इसमें अधिकतर निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं जिसमें प्रत्येक देश को एक मत प्राप्त होता है। यूरोपीय केन्द्रीय बैंक के प्रमुख कार्य हैं: मुद्रा चलन की मात्रा का प्रबंधन, विदेश विनिमय कार्य सम्पादन, सदस्य-राज्यों के सरकारी मुद्रा भण्डारों का रखरखाव एवं प्रबंधन, तथा अदायगी व्यवस्था को सरल बनाना। यूरो क्षेत्रों में बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार यूरोपीय केन्द्रीय बैंक के पास है। यह केन्द्रीय बैंकों की यूरोपीय व्यवस्था का केन्द्र बिन्दु है।

आर्थिक एवं मौद्रिक संघ का तीसरा चरण 1 जनवरी 1999 में यूरो के चलन तथा मौद्रिक सत्ता का यूरोपीय केन्द्रीय बैंकों के हस्ताक्षर के साथ आरंभ हुआ। मई 1998 में ही यूरोपीय संघ के शिखर सम्मेलन में यह निश्चित हो गया था कि यूरोपीय संघ के 15 में से 11 देश (जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, आयरलैण्ड, इटली, लक्ज़मबर्ग, नीदरलैण्ड, आस्ट्रिया, पुर्तगाल, फिनलैण्ड तथा बेल्जियम) एकल मुद्रा अपना देने के मानदण्ड पर खरे उतरे हैं। 1 जनवरी 1999 को इन देशों ने यूरो को सांझी मुद्रा के रूप में अपना लिया। निश्चित मानदण्डों को पूरा करने के बाद 1 जनवरी 2001 में ग्रीस ने भी यूरो को अपना लिया। स्वीडन ये मानदण्ड पूरे नहीं कर सका डेनमार्क तथा ब्रिटेन "विशेष स्थिति के सदस्य-राज्य

(Member-states with special status) हैं। इन देशों को आर्थिक एवं मौद्रिक संघ के तीसरे चरण में (अर्थात् यूरो को अपनाने में) भाग न लेने का निर्णय लेने की छूट दी गई। इन दोनों ने इस विकल्प का लाभ उठाया तथा यूरो क्षेत्र से बाहर रहने का निर्णय लिया। क्योंकि स्वीडन तथा अन्य दस देशों ने यूरो अपनाने से सम्बन्धित मानदण्ड पूरे नहीं किए थे, इन्हें यूरोपीय संघ के "अप्रतिष्ठित राज्य (Members with derogation) की संज्ञा दी जाती है। इसका अर्थ है कि यूरोपीय संघ के तीसरे चरण में लागू हुए प्रावधानों में से केवल कुछ, न की सभी, प्रावधानों से छूट दी गई है। जैसे स्वीडन तथा अन्य नए दस राज्यों (जिन्हें 1 मई 2004 में सम्मिलित किया गया) के पास ब्रिटेन तथा डेनमार्क की तरह बाहर रहने का विकल्प नहीं है, अर्थात् यूरोपीय संघ का सदस्य बनने के बाद ये नए राज्य यूरो को अपनाने के लिए कटिबद्ध हैं।

1 जनवरी 1999 में विनिमय दर रचनातंत्र (द्वितीय) (ERM-II) की स्थापना की गई। यह यूरो व्यवस्था तथा जिन देशों ने यूरो को नहीं अपनाया के बीच विनिमय दर नीति में समन्वय का ढाँचा प्रदान करता है। इसकी सदस्यता ऐच्छिक है परन्तु यह यूरोपीय सदस्य-राज्यों तक सीमित है। ऐसी आशा की जाती है कि यूरोपीय संघ के अप्रतिष्ठित राज्य भी इसमें सम्मिलित होंगे। वास्तव में यूरो को अपनाने से पहले सदस्य देशों की मुद्रा दो साल तक विनिमय दर रचनातंत्र (द्वितीय) के अन्तर्गत रहती है। इस रचनातंत्र के कार्य हैं: यूरो के मुकाबले प्रत्येक देश की मुद्रा की विनिमय दर की केन्द्रीय दर निश्चित करना तथा इस केन्द्रीय दर के दायरे में उतार-चढ़ाव की उच्च तथा निम्न सीमा निर्धारण करना। इसका अर्थ यूरोपीय केन्द्रीय बैंक के साथ समन्वय स्थापित करना भी है। अभी तक गैर-यूरो क्षेत्र के 13 यूरोपीय संघ के सदस्यों में से 8 देश विनिमय दर रचनातंत्र (द्वितीय) के सदस्य हैं – डेनमार्क, इस्टोनिया, लिथुनिया, स्लोवेनिया, साईप्रस, लैटविया, माल्टा तथा स्लोवाकिया। आशा है कि ये देश 2007 अथवा 2008 में यूरो क्षेत्र में सम्मिलित कर लिए जाएँगे। जो देश अभी भी यूरो क्षेत्र से बाहर हैं, वे हैं : चेक गणराज्य, हंगरी, पोलैण्ड, स्वीडन तथा ब्रिटेन।

इस चरण में एक और समझौता *स्थायित्व एवं वृद्धि पैक्ट* (Stability Growth Pact; SGP) लागू किया गया। *स्थायित्व एवं वृद्धि पैक्ट* 1997 में अपनाया गया और इसके सभी

प्रावधान 1 जनवरी 1999 में लागू किए गए। इस पैक्ट का मुख्य उद्देश्य वित्तीय अनुशासन को आर्थिक एवं मौद्रिक संघ का स्थायी अंग बनाना है। अन्य उद्देश्य हैं : कीमतों में स्थिरता, विकास तथा रोजगार के लिए ठोस सरकारी वित्तीय सहायता का सुरक्षा कवच स्थापित करना। प्रारंभ में स्थायित्व एवं वृद्धि पैक्ट के तीन तत्व थे: (1) राजनीतिक कटिबंधता अर्थात् यूरोपीय आयोग, सदस्य देश तथा परिषद् सभी की बजट निरीक्षण प्रक्रिया को सम्पूर्ण रूप में तथा समय पर पूरा करना। (2) निवारक तत्व अर्थात् किसी भी देश के बजट घाटे को तीन प्रतिशत से अधिक न होने के निवारक उपाय सुझाना, तथा (3) निवर्तक (Dissuasive) तत्व अर्थात् यदि किसी देश के बजट घाटे की सीमा 3 प्रतिशत की सीमा टूट जाती है तो उसे तुरन्त सुधारक उपाय करने के लिए मजबूर किया जाए और यदि आवश्यकता पड़े तो दण्ड भी दिया जाए। इन कानूनी आधारों के साथ-साथ सदस्य देशों को उनके आर्थिक कार्यक्रम तैयार करने में सहायता करने के लिए आचार संहिता का भी प्रावधान किया गया।

तालिका 2 : आर्थिक व मौद्रिक संघ के तीन चरण

प्रथम चरण 1 जुलाई 1990	द्वितीय चरण 1 जनवरी 1994	तृतीय चरण 1 जनवरी 1999
पूँजी आदान-प्रदान के लिए पूर्ण स्वतंत्रता	यूरोपीय वित्तीय संस्थान की स्थापना	स्थायी बदलाव दरें निश्चित करना
केन्द्रीय बैंकों में उत्तरोत्तर सहयोग	केन्द्रीय बैंकों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्रों को ऋण देने पर मनाही	यूरो की शुरुआत
यूरोपीय मुद्रा इकाइयों (European Currency Units) (यूरो) का मुक्त प्रयोग	आर्थिक अभिसरण को शक्तिशाली बनाना	केन्द्रीय बैंकों की यूरोपीय व्यवस्था द्वारा एक वित्तीय नीति का संचालन
आर्थिक अभिसरण (Convergence) से सुधार	राष्ट्रीय केन्द्रीय बैंकों की स्वतंत्रता प्रक्रिया आरंभ जिसे केन्द्रीय बैंकों की यूरोपीय व्यवस्था की स्थापना तक पूरा करने का लक्ष्य था	आन्तरिक विनिमय दर व्यवस्था का लागू होना

	तीसरे चरण की तैयारी	स्थायित्व एवं वृद्धि पैकट को लागू किया गया।
--	---------------------	---

स्रोत: <http://www.ecb.int/ecb/history/emu/html/index.en.html>

हालाँकि यूरो बैंक नोट तथा सिक्के 1 जनवरी 2002 से प्रचलन में आए, हिसाब-किताब की मुद्रा के रूप में इसे 1 जनवरी 1999 में ही लागू कर दिया गया था। 1 जनवरी 1999 तथा 1 मार्च 2002 के बीच कई तरह के प्रारंभिक कदम उठाए गए (जब सभी राष्ट्रीय नोट तथा सिक्के वापस ले लिए गए)। एकल मुद्रा लागू करने वाले देशों ने निर्णय लिया कि इन भागीदार देशों की उस समय की विनिमय दर रचनातंत्र द्विपक्षीय दरें यूरो की परिवर्तन दरें निश्चित करने के लिए प्रयुक्त की जाएगी।

तालिका 3 : यूरो विनिमय दरें (Euro Conversion Rates)

एक यूरो बराबर है

40.3399	बैल्जियम फ्रैंक	13.7603	आस्ट्रियन शीलिंग	1936.27	इटैलियन लारा
1.666386	स्पेनिश पिस्तास	5.94573	फिन्सिस मार्क्स	2.20371	डच गिलंडर
0.787564	आइरिष पन्त	1.95583	जरमन मार्क	200.482	पुर्तगाली इसकोडस
40.3399	लग्ज़मबर्ग	6.55957	फ्रेन्चफ्रेन्क	390.750	प्रतीक ड्राचमा

अन्य तैयारियाँ थी – सभी सार्वजनिक ऋणों का यूरो में नामकरण, यूरोपीय केन्द्रीय बैंकों की सभी कार्यविधियों को यूरो में बदलना, वित्तीय तथा पूँजी बाजारों में यूरो का बड़े पैमाने पर प्रयोग, निजी बैंक खातों का यूरो में नामकरण, यूरो नामकरण के क्रेडिट कार्य उपलब्ध करवाना, तथा वर्तमान ऋण-कार्यों पर यूरो द्वारा भुगतान संभव बनाना, यूरो लागू करने वाले देशों में निजी कम्पनियों को हिसाब-किताब, टैक्स अदायगी, सामाजिक सुरक्षा भुगतान आदि में यूरो के प्रयोग की इजाजत देना तथा आम जनता को यूरो अपनाने के लिए तैयार करने के लिए दोहरी कीमत प्रणाली – राष्ट्रीय मुद्रा तथा यूरो लागू करना।

7.5 यूरो के लाभ

यूरोप में एकल मुद्रा लागू करने के कई उद्देश्य थे – इसका पहला, उद्देश्य यूरोप को और अधिक प्रतिस्पर्धात्मक तथा गतिशील बनाना था तथा यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के बीच रोजगार तथा विकास के अवसर बढ़ाना था। यूरोपीय संघ के अन्दर विनिमय दरों की अनिश्चितता तथा संक्रमण कीमतों के समाप्त होने से सूक्ष्म अर्थशास्त्र के लाभ बढ़ने की आशा बढ़ गई है जिसके परिणामस्वरूप व्यापार को प्रोत्साहन मिलेगा तथा उत्पादन में स्थायी वृद्धि हो सकेगी। इसी तरह आन्तरिक-यूरोपीय संघ विनिमय दरों की समाप्ति तथा मौद्रिक एवं वित्तीय नीतियों में अनुशासन लाने के परिणामस्वरूप सूक्ष्म अर्थशास्त्रीय कुशलता में भी वृद्धि होने की आशा है जो ब्याज दरों की अनिश्चितता को कम करके अधिक निवेश के अवसर बढ़ा सकता है। यूरो का दूसरा उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की एक ऐसी स्थाई मुद्रा स्थापित करना है जो अमरीकी डॉलर तथा जापान के येन का मुकाबला कर सकें।

क्योंकि आर्थिक तथा मौद्रिक संघ का निर्माण श्रेष्ठ आर्थिक प्रबंधन के नियमों पर हुआ था, अतः आशा की गई है कि समूचे संसार की कम्पनियाँ (केवल यूरोप की ही नहीं) इस यूरोपीय विकास का लाभ उठाएँगी। यूरो का चलन अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था के स्थायित्व में भी योगदान कर सकता है।

यूरो क्षेत्र की आर्थिक विशेषताओं, इसके आकार तथा इसके वित्तीय बाज़ार के संघटन को ध्यान में रखते हुए यह यूरोपीय मुद्रा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा बाज़ार में निष्चय ही प्रमुख खिलाड़ी बनने जा रही है। विष्व स्तर पर यूरो के दो लाभ हैं। यह संपूर्ण यूरोप में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा के उतार-चढ़ाव के प्रभाव को कम करेगा। दूसरा यह अमेरिकी डॉलर के अन्तर्राष्ट्रीय प्रभुत्व में उत्तरोत्तर कमी ला सकता है। इससे यूरोपीय आर्थिक नीतियों के वृहतर अन्तर्राष्ट्रीयकरण की संभावना भी बढ़ गई है। यूरो के महत्वपूर्ण लाभों को निम्न तालिका द्वारा दर्शाया जा सकता है:

तालिका 4 : यूरो के लाभ (Table 4: Benefits of EURO)

नागरिकों के लिए व्यावहारिक लाभ (Practical Benefits for Citizens)

- यूरो क्षेत्र के अंदर यूरो क्षेत्रीय नागरिक अपनी मुद्रा का प्रयोग कर सकते हैं।

- अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा होने के कारण इसे सब जगह स्वीकार किया जाता है।

व्यापक सूक्ष्म आर्थिक लाभ

- कीमतों में स्थिरता
- स्वस्थ सार्वजनिक वित्त
- कम ब्याज दर
- निवेश, रोजगार तथा विकास के लिए प्रोत्साहन
- विदेशी संकटों से शरण

एकल बाज़ार (Single Market)

- विनिमय दरों की अस्थिरता से छुटकारा
- अनिश्चितताओं की कमी के कारण नीति-निर्णय में आसानी
- विभिन्न लेन-देन सम्बन्धी कीमतों की छुट्टी नीति-निर्णय में आसानी (जैसे सीमापार शुल्क, विभिन्न मुद्राओं का हिसाब-किताब रखना आदि)
- कीमतों में पारदर्शिता
- प्रतिस्पर्धा में बढ़ोतरी
- उपभोक्ता के लिए अधिक अवसर
- विदेशी निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक अवसर

एकल वित्तीय बाज़ार

- वित्तीय कार्यकर्ताओं के लिए एकल बाज़ार (जैसे बैंक, बीमा कम्पनियाँ, निवेशक धन, पेन्शन कोष, आदि)
- निजी तथा कम्पनी स्तर पर ऋण लेने वालों के लिए बेहतर निधी के अवसर
- बचतधारियों के लिए निवेश तथा बचत के व्यापक तथा विभिन्न अवसरों का बजटधारी को लाभ/तथा निवेशकों के लिए अपनी पूँजी लगाने के लिए पूँजी अवसर।

संसार में यूरो की भूमिका (Role of Europe in the World)

- यह अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं (जैसे अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ओ.ई.सी.डी. तथा विष्व बैंक में यूरोप की भूमिका को शक्तिशाली बनाता है।
- निवेश तथा आरक्षित मुद्रा के रूप में यूरो की महत्वपूर्ण भूमिका
- अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में यूरो का प्रयोग
- वस्तुओं तथा सामान (जैसे तेल, धातु आदि) की यूरो में कीमत लगाने का विकल्प।

राजनीतिक एकीकरण (Political Integration)

- यूरो सांझी अस्मिता, सांझे मूल्यों तथा यूरोपीय एकता की सफलता का प्रतीक
- अधिक एकीकरण के लिए प्रेरणा।

स्रोत: यूरोपियन आयोग के यूरो वेबसाईट से लिया गया।

कई विद्वानों ने इस प्रक्रिया की आलोचना की है। उनका मानना है कि यूरो का चलन वित्तीय मामलों में राष्ट्रीय प्रभुसत्ता पर प्रहार है। *स्थायित्व एवं वृद्धि पैक्ट* (Stability Growth Pact; SGP) जैसे कड़े समझौतों के कारण विभिन्न देश आर्थिक परिस्थितियों के प्रतिकूल प्रभावों से अपने आपको बचा नहीं पायेंगे। यह आर्थिक एवं मौद्रिक संघ समुदाय में प्रवेश से इसकी विभिन्न व्यापारिकों के प्रतिकूल प्रभावों से अपने आपको बचा नहीं पाएँगे। यह आर्थिक एवं मौद्रिक संघ” संघ को अन्तरंगी (insider) तथा बाहरी (outsider) देशों में बांट देगी। इसी तरह अपेक्षाकृत कम विकसित राज्यों के यूरोपीय समुदाय में प्रवेश से इसकी विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में अत्याधिक असमानता आ जाएगी जिनके लिए आर्थिक एवं मौद्रिक संघ जैसी सांझी नीतियाँ काफी कठोर हो सकती है।

7.6 विष्व अर्थव्यवस्था में यूरो

यूरो के आगमन से पहले कई तरह के अध्ययनों तथा संवेक्षणों की राय थी कि यह एक प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में उभरेगा। इसके अनेक कारण थे। सर्वप्रथम, यूरो क्षेत्र की अर्थव्यवस्थाओं का आर्थिक आकार अमेरिका के बराबर तथा जापान से कहीं अधिक था। दूसरे, यूरोक्षेत्र (Eurozone) वस्तुओं तथा सेवाओं का सबसे बड़ा आयातक (importers) तथा निर्यातक (exporters) क्षेत्र है। तीसरे, यूरोपीय संघ के अन्दर स्थायित्व उन्मुखी आर्थिक नीति ढाँचा यूरो को एक आकर्षक मुद्रा बनाने में कारगर होगा। अंत में, यूरो यूरोप की कई प्रमुख कानूनों, मुद्राओं, जैसे ड्यूष मार्क की अन्तर्राष्ट्रीय भूमिका का उत्तराधिकारी बनने जा रही थी।

तालिका 5 में किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा का मानक प्रयोग सारांश रूप में दिया गया है जो अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर (सरकारी तथा निजी दोनों क्षेत्रों) मुख्यतः तीन परम्परागत कार्यों पर आधारित है: खाते की इकाई, विनिमय का साधन तथा मूल्य का भण्डार।

तालिका 5

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा के कार्य

	निजी क्षेत्र	सरकारी क्षेत्र
खाते की इकाई	व्यापार तथा वित्तीय लेन-देन का बीजक (invoice) बनाना, वस्तुओं की कीमतों के निवेदित (quotation) भाव	विनिमय दर प्रणाली की स्थिरता अथवा सांकेतिक मुद्रा।
विनिमय का साधन	अदायगी मुद्रा, विदेशी मुद्रा बाज़ार की चलायमान मुद्रा	विदेशी मुद्रा बाज़ार में सरकारी हस्तक्षेप, सरकारी वित्तीय प्रवाह
मूल्य का भण्डार	निवेश तथा वित्तीय मुद्रा।	विदेशी विनिमय भण्डार मुद्रा।

स्रोत: ई एम यू: दी फर्स्ट टू यीयर्स, यूरो पेपर्स संख्या 42 (ब्रस्सल्स, यूरोपीय आयोग, 2001)।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा के उपरोक्त परम्परागत कार्यों के आधार पर यदि हम यूरो की भूमिका का मूल्यांकन करें तो हम पाते हैं कि इसका प्रभाव दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, हालाँकि उतना नहीं जितना की यह अन्य क्षेत्रों में है। यूरोपीय केन्द्रीय बैंक द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार, पिछले पाँच वर्षों में यूरो की भूमिका में धीरे-धीरे वृद्धि हुई है। यूरो क्षेत्र के आस-पास के राज्यों में यह प्रमुख मुद्रा है। अन्तर्राष्ट्रीय ऋण तथा बाज़ार में भी इसका महत्वपूर्ण विकास हुआ है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तक विदेशी विनियम बाज़ारों में भी यह धीरे-धीरे विकसित हो रहा है। यह यूरोप की पुरानी मुद्राओं द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका का सही उत्तराधिकारी सिद्ध हो रहा है। एक भण्डार मुद्रा के रूप में इसकी साख कुछ बढ़ी ही है। एशिया तथा विकासशील देशों में अन्तर्राष्ट्रीय वित्त प्रबंधन की मुद्रा तथा भण्डार के रूप में डॉलर अभी भी प्रधान है।

अन्तर्राष्ट्रीय ऋण बाज़ार तक यूरो खाते में नामांकित प्रत्याभूतियाँ कुल अन्तर्राष्ट्रीय भण्डार का 31 प्रतिशत है। इनमें से भी अधिकतर भाग यूरो खाते में स्थित यूरोपीय इकाइयों का है। अन्तर्राष्ट्रीय ऋण तथा जमा खातों में भी समान प्रवृत्ति दिखाई देती है। अन्तर्राष्ट्रीय ब्राण्ड बाज़ार में वित्त प्रबंधीय मुद्रा के रूप में यूरो के प्रयोग में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। अन्तर्राष्ट्रीय विदेशी विनियम बाज़ारों के व्यापारिक लेन-देन में 2004 में यूरो दूसरे स्थान पर था जो कुल अन्तर्राष्ट्रीय लेन-देन का 37 प्रतिशत था। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में यूरो क्षेत्र के राज्यों में यूरो के प्रयोग में विशेष वृद्धि देखने को मिली है। इन देशों में भी यूरो का प्रयोग निर्यात के लिए अधिक तथा आयात के लिए कम हो रहा है। इसके अलावा यूरोपीय संघ के नए सदस्य तथा सदस्यता के लिए प्रार्थी देशों में भी यूरो का चलन बढ़ रहा है। यूरो क्षेत्र से बाहर अन्य देशों में भी एक स्थिर मुद्रा के रूप में यूरो की भूमिका महत्वपूर्ण है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा सूचित स्वायत्त चल पूँजी वाले 150 देशों में से 40 से अधिक देश यूरो को एक स्थिरण तथा सांकेतिक मुद्रा के रूप में प्रयुक्त कर रहे हैं। यदि इन देशों का ध्यान से विप्लेषण करें तो पता चलता है कि इनमें से अधिक देश या तो यूरो क्षेत्र के काफी नजदीक हैं या इन्होंने यूरो क्षेत्र के देशों के साथ विशेष संस्थागत प्रबंध स्थापित किए हुए हैं। विष्व विदेशी मुद्रा भण्डार में यूरो का अंश सन् 2000 में 16.3

प्रतिषत था जो 2003 में बढ़कर 19.7 प्रतिषत हो गया है। एक हस्तक्षेपी मुद्रा के रूप में भी यूरो का प्रयोग यूरो क्षेत्र के पड़ोसी देशों के साथ खुलकर हो रहा है।

7.6.1 यूरो तथा भारत

क्योंकि यूरोपीय संघ भारत का प्रमुख वाणिज्यिक हिस्सेदार तथा निवेश एवं तकनीक हस्तान्तरण का महत्वपूर्ण स्रोत हैं, अतः यूरो क्षेत्र की अर्थव्यवस्थाओं तथा यूरो की निष्पत्ति का भारत यूरोपीय संघ व्यापार तथा आर्थिक सम्बन्धों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। अभी तक भारत के विदेश व्यापार का 80-85 प्रतिषत लेन-देन डॉलर के माध्यम से हो रहा था परन्तु अब ऐसे संकेत हैं कि यह आदान-प्रदान यूरो, विशेषतः भारत यूरोपीय संघ व्यापार, में भी होने लगा है। परन्तु इसका प्रभाव अभी बहुत कम है क्योंकि ब्रिटेन अभी यूरो क्षेत्र से नहीं जुड़ा है तथा भारत के दो महत्वपूर्ण आयात – पेट्रोलियम तथा खाद – अभी डॉलर से ही जुड़े हुए हैं। यूरो के चलन से पहले ऐसी आशा की जा रही थी कि यूरो द्वारा विमुक्त सकारात्मक आर्थिक शक्तियों के परिणामस्वरूप भारत तथा यूरोप के बीच नजदीकी व्यापारिक रिश्तों की भावनाएँ बढ़ेगी परन्तु अभी तक यूरो क्षेत्र की व्यापारिक धीमी गति की आर्थिक प्रगति ने यूरो की सफलता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। 2003-04 में यूरो के शक्तिशाली होने से भारत में इसके प्रति रुचि बढ़ी तथा भारत ने इसे एक और अतिरिक्त हस्तक्षेपी मुद्रा के रूप में घोषित कर दिया है। ऐसी संभावना है कि भारत के 143 अरब डॉलर के विदेशी मुद्रा भण्डार में यूरो काफी मात्रा में होगा। भारत की अर्थव्यवस्था तथा व्यापार के संदर्भ में यूरो की भूमिका, सीमित परन्तु सकारात्मक, है। दीर्घकालीन दृष्टिकोण से देखें तो एक स्थायी अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में यूरो का उदय तथा यूरो क्षेत्रों में विकास एवं कीमतों में स्थिरता जैसे कारक भारत की अर्थव्यवस्था तथा व्यक्तिगत व्यापार के लिए कई नए अवसर प्रदान कर सकते हैं। केन्द्रीय तथा पूर्वी यूरोप के देशों के साथ व्यापारिक आर्थिक सम्बन्ध सुधारने में यूरो भारत की सहायता कर सकता है। यूरो की सफलता एशिया/दक्षिण एशिया के लिए भी एकल मुद्रा का प्रेरणा स्रोत बन सकता है।

7.7 सारांश

पिछले 50 सालों में यूरोपीय संघ के देशों में अलग-अलग मौद्रिक व्यवस्था रही जैसे ब्रैटन-वुड्स व्यवस्था, सुरंग में सांप, यूरोपीय मौद्रिक व्यवस्था, तथा आर्थिक एवं मौद्रिक संघ, कई प्रस्तावों के बाद 1992 में मैस्ट्रिक संधि के अधीन आर्थिक तथा मौद्रिक संघ की स्थापना हुई जिसने यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के लिए मुद्रा के एकीकरण की दिशा निर्देश को सुझाया। आर्थिक एवं मौद्रिक संघ की स्थापना के लिए प्रगति तीन चरणों में हुई। यूरो अपनाने वाले देशों को मुद्रा परिवर्तन सम्बन्धी मानदण्डों को पूरा करना आवश्यक था। 1999 में 11 देशों ने यूरो अपनाया। ग्रीस ने इसे बाद में अपनाया। यूरो का चलन 1 जनवरी 2002 में आरंभ हुआ। ब्रिटेन तथा डेनमार्क ने “बाहर रहने के विकल्प” का प्रयोग करते हुए आर्थिक एवं मौद्रिक संघ के तीसरे चरण में हिस्सा नहीं लिया। विनिमय दर रचनातंत्र (द्वितीय) (ERM-II) यूरो व्यवस्था तथा यूरो न अपनाने वाले यूरोपीय संघ के सदस्यों के बीच विनिमय नीति सहयोग का ढाँचा प्रदान करती है। प्रचलन से लेकर आज तक अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एवं निवेश विनिमय बाजार में भी यूरो का विकास महत्वपूर्ण रहा है। भारत के साथ व्यापार के संदर्भ में अभी तक के संकेत सकारात्मक हैं हालाँकि ये सीमित हैं। दीर्घकालीन दृष्टिकोण से भारतीय व्यापार के लिए ये कई नए सार्थक एवं महत्वपूर्ण अवसर प्रदान कर सकते हैं।

7.8 अभ्यास प्रश्न

- 1) क्षेत्रीय आर्थिक प्रबंधों के विभिन्न चरण क्या हैं?
- 2) आर्थिक तथा वित्तीय संघ के विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए।
- 3) यूरोप के लिए एकल मुद्रा के लाभों की व्याख्या कीजिए।
- 4) यूरो की अन्तर्राष्ट्रीय भूमिका पर लेख लिखिए।
- 5) यूरोप की एकल मुद्रा का भारत के लिए क्या परिणाम हैं?
- 6) संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए:
 - (i) ब्रैटन-वुड्स व्यवस्था
 - (ii) यूरोपीय केन्द्रीय बैंक

- (iii) विनिमय दर रचनातंत्र (द्वितीय) (ERM-II)
- (iv) स्थायित्व एवं वृद्धि पैक्ट

7.9 संदर्भ तथा कुछ उपयोगी पुस्तकें

बाल्डविन, रिचर्ड एवं चार्ल्स विहप्लोज़, *इकॉनामिक्स ऑफ यूरोपियन इंटीग्रेशन* (मैकग्रा हिल, 2003)।

अल-अजरा, अली एम., *दी यूरोपियन यूनियन : इकॉनामिक्स ऑफ पालिसिज*, (सातवाँ संस्करण) (हारलो (यू.के.) आदि : फाइनेषियल टाइम्स/प्रेन्टिस हॉल, 2004)

यूरोपियन सेंट्रल बैंक, *रिव्यू ऑफ दी इंटरनेशनल रोल ऑफ दी यूरो* (फ्रैंकफर्ट : ई सी बी : 2005)

जोन्स, राबर्ट ए, *दि पॉलिटिक्स एंड दी इकॉनामिक्स ऑफ दी यूरोपियन यूनियन : एन इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट* (चीलटेनहेम, नार्थएम्पटसन, एडवर एलजर, द्वितीय संस्करण, 2001)।

डायरेक्टरेट जनरल ऑफ दी इकॉनामिक एंड फाइनेषियल एफैयर्स ऑफ दी यूरोपियन कमीशन।

http://ec.europa.eu/economy_finance/index.en.htm

यूरोपियन सैन्ट्रल बैंक www.ecb.int

